

प्रेषक,

आर०के० सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 31 मार्च, 2015

विषय:- जनपद पौड़ी के गहड़ में प्रस्तावित राजकीय जी०एन०एम० स्कूल के निर्माण के प्रथम चरण कार्य हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26प/चि०शि०/110/2013/1525 दिनांक 19 मार्च, 2015 के कम में जनपद पौड़ी के गहड़ में राजकीय जी०एन०एम० स्कूल के निर्माण के प्रथम चरण कार्य हेतु टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 21.77 लाख (₹ इक्कीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष इतनी ही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट से व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- i. उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- ii. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों के अनुरूप है एवं तदनुसार ही सम्पादित किये जायेंगे।
- iii. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है परन्तु धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया हो एवं स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
- iv. उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आवश्यक धनराशि एम०ओ०यू० के निष्पादन के बाद अवमुक्त की जा सकेगी। कार्य एम०ओ०यू० में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम०ओ०यू० में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुनरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा तथा परियोजनाओं को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रश्नगत नवीन कार्य हेतु B.M.80 के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए द्वितीय चरण के कार्य हेतु विस्तृत आगणन (D.P.R) के गठन एवं अन्य संबंधित कार्यों के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, नवीन बजट मैनुअल के प्रस्तर-182(छः) आलोक में सम्यक् परीक्षणोपरान्त संगत योजनान्तर्गत पूर्व स्वीकृत चालू कार्यों के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

क्रमशः पेज-02.....

- v. कार्यदायी संस्था को डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्य एवं साज सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार शासनादेश सं०-163/XXVII(7)/2007 दिनांक 22.05.2008 एवं इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग के नवीनतम शासनादेशों के अनुसार देय होगा ।
- vi. कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- vii. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
- viii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- ix. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मँददेनजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- x. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए ताकि निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
- xi. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
- xii. यद्यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।
- xiii. प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजायन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है या वर्तमान कार्य में एक भाग की डिजायन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।
- xiv. द्वितीय चरण के विस्तृत आगणन को प्रेषित करते समय यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये कि "प्रथम चरण के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो चुके हैं"।
- xv. उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार एवं कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति के आधार पर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।
- xvi. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- xvii. आगणन को जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
- xviii. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या हर दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
- xix. कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि योजना हेतु किये जाने वाले कार्य आवंटन/निविदा/आउटसोर्स आदि की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु समय-समय पर सूचनाएँ चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी।
- xx. धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-11-नर्सिंग स्कूल की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत मानकों के नामें डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-513(P)/XXVII(3)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
- 3- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 6- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 7- परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर इकाई-1, मेडिकल कॉलेज कैम्पस, श्रीनगर गढ़वाल।
- 8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
- 9- वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- बजट प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय कैम्पस, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एस0 डुमरियाल)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Medical Education (S031)

आवंटन पत्र संख्या - 363/XXVIII(1)/2015-89/2012

अनुदान संख्या - 012

अलोटमेंट आई डी - S1503121036

आवंटन पत्र दिनांक - 31-Mar-2015

HOD Name - Director Medical Education (2645)

- 1: लेखा शीर्षक 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105 - एलौपैथी 11 - नर्सिंग स्कूल की स्थापना
00 - नर्सिंग स्कूल की स्थापना

मानक मद का नाम	Plan Voted		
	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	96974000	2177000	99151000
	96974000	2177000	99151000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

2177000

(एनएसओ डुगरियाल)
उप सचिव।